बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 139 ● नई दिल्ली ● सोमवार 16 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

फोजन एम्ब्रियो को लेकर पति-पत्नी में कानूनी जंग, 16 भ्रूणों के लिए हाईकोर्ट पहुंची महिला

नई दिल्ली । मुंबई की एक महिला ने अपने अलग रह रहे पति के साथ चल रहे विवाद के बीच जमे हुए भ्रूणों (फ्रोजन एम्ब्रियो) के अधिकार को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बताया जा रहा है कि महिला के पास कुल 16 भ्रूण संरक्षित हैं, जिनके इस्तेमाल को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है. इससे पहले राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड ने उसकी इस अपील को खारिज कर दिया था. 46 साल की यह महिला पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में भी गई थी, लेकिन सितंबर 2025 में उसने अपनी याचिका वापस ले ली थी ताकि वह दिल्ली में संबंधित बोर्ड से अपील कर सके. मगर महिला का आरोप है कि उसकी अपील को सही तरह से सुने बिना खारिज कर दिया गया.

गैस सिलेंडर की जमाखोरी पर सख्ती, अफवाह फैलाने वालों पर सरकार का एक्शन- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर सामने आ रही खबरों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी गैस सिलेंडरों की जमाखोरी की शिकायत मिलती है तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है कि वे लोगों के बीच डर का माहौल बनाने से बचें।

लोगों से संयम रखने की अपील

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि संकट के समय सभी नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में गैस सिलेंडरों को छिपाकर रखा जा रहा है या जरूरत से ज्यादा जमा किया जा रहा है, तो सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश जब किसी कठिन परिस्थिति से गुजरता है, तब सभी को एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं और उन्हें जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने के लिए उकसा रहे हैं, जो कि गलत है।

अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी

रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अफवाहें फैलाना देशहित के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से अपील

की कि वे धैर्य रखें और जरूरत के अनुसार ही गैस का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे और गैस सप्लाई व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगी।

गैस सिलेंडर की कमी से लोग परेशान

इधर, राजधानी के कुछ इलाकों में गैस सिलेंडरों की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। Sonia Vihar की रहने वाली खुशनुमा ने बताया कि बाजार में कुछ लोग गैस सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं और इसके लिए करीब 4500 रुपये तक मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा कीमत देना संभव नहीं है, इसलिए मजबूरी में घर की छत पर चूल्हा बनाकर खाना बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि Eid al-Fitr भी करीब है। वहीं एक अन्य निवासी सलीम ने बताया कि पहले जो व्यक्ति उनके लिए गैस सिलेंडर लाकर देता था, उसका फोन अब बंद आ रहा है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सिलेंडर कब और कैसे मिलेगा। सोशल मीडिया पर भी कई लोग यह शिकायत कर रहे हैं कि गैस बुकिंग कराने के बावजूद समय पर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है।

आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन

इस बीच विपक्षी दल Aam Aadmi Party ने इस मुद्दे को लेकर राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष Saurabh Bharadwaj ने बताया कि शहर के करीब 250 स्थानों पर गैस सिलेंडर शोभायात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजधानी में गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है और लोग अब इसके ÷दुर्लभ दर्शन÷ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा हालात उसी का परिणाम हैं।

गंगा किनारे अतिक्रमण पर विस्तृत रिपोर्ट दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह गंगा नदी के किनारों और बाढ़ के मैदानों पर हुए अवैध निर्माणों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे और अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी भी दे। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार से गंगा के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित अधिसूचना के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए अब तक उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड पर रखने को कहा। पीठ ने कहा, ऊपर बताए गए नोटिफिकेशन को बेहतर और प्रभावी ढंग से लागू करने में अथॉरिटी के रास्ते में कौन सी रुकावटें या बाधाएं आ रही हैं? ऊपर बताए गए सभी राज्यों से होकर बहने वाली गंगा नदी की सुरक्षा के लिए अथॉरिटी क्या कदम उठाने का इरादा रखती है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करेगी कि नदी के मैदान और किनारे सभी तरह के अतिक्रमणों से मुक्त हों?

अदालत ने गंगा बेसिन के कई राज्यों को नोटिस जारी किए और कहा कि इस मुद्दे के लिए अलग-अलग मामलों से परे एक व्यापक जांच की आवश्यकता है। यह मामला अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल को सूचीबद्ध है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील आकाश वशिष्ठ ने दलील दी कि नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है, जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नदी के इन किनारों के कुछ हिस्सों में ताजे पानी की डॉल्फिन बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी जानना चाहा कि गंगा नदी के मैदानी इलाकों और किनारों को सभी तरह के अतिक्रमणों से पूरी तरह मुक्त करने वाली अधिसूचना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्राधिकरण इस अदालत से किस तरह के निर्देश चाहता है। शीर्ष अदालत पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने एनजीटी के 30 जून, 2020 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एनजीटी ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील बाढ़ के मैदानों पर अवैध निर्माण और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

सुल्तानपुरी थाने में सीबीआई की छापेमारी, तीन पुलिसकर्मी गिरफ्तार

सड्डा-फड्डा चलवाने के लिए 20,हजार रूपे की रिश्वत लेते हुए हवलदार,अजय कुमार, राजेश और विजय मालिक सहित तीनों पॉलिसकर्मि धर दबोचा.

नई दिल्ली,(ए.के.चौधरी) बाहरी ज़िले के थाना सुल्तानपुरी में सीबीआई ने अचानक छापेमारी कर तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार पुलिसकर्मियों में हेड कांस्टेबल अजय कुमार, राजेश और कांस्टेबल विजय मलिक शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने इलाके में सड्डा-फड्डा चलाने की अनुमति देने के बदले 20 हज़ार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर MCD स्टोर वार्ड 44 से रंगे हाथों कार्यवाही और तीनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया. स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से सुल्तानपुरी में कुकुरमुत्तों की

तरह गली-गली में सड्डा- फड्डा और शराब, गंज नशीले इंजेक्शन का करोबर खुलेआम हो रहा है. फिलहाल, सीबीआई की टीम तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

22 मार्च को दिल्ली में नेशनल लोक अदालत होगी आयोजित, लंबित ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 22 मार्च 2026, रविवार को 'नेशनल लोक अदालत' आयोजित की जा रही है. इस विशेष पहल के तहत दिल्ली के विभिन्न न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को अपने लंबित चालान और नोटिसों का निपटारा कराने का अवसर मिलेगा. इस पहल का उद्देश्य लोगों को एक ही दिन में अपने लंबित चालान या नोटिस का समाधान कराने की सुविधा देना है. जिन वाहन चालकों के ट्रैफिक चालान या नोटिस लंबित हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं. लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 22 मार्च, 2026 (रविवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। 22 मार्च को दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर शामिल हैं. इन सभी स्थानों पर निर्धारित समय के दौरान ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारा किया जाएगा. लोक अदालत में पेश होने से पहले संबंधित चालान या नोटिस को डाउनलोड करना जरूरी होगा. लोक अदालत से जुड़े नोटिस और चालान 16 मार्च 2026 की सुबह 10 बजे से पोर्टल पर उपलब्ध होंगे. यह सुविधा तब तक जारी रहेगी जब तक कुल 2 लाख नोटिस जारी नहीं हो जाते. प्रतिदिन अधिकतम 50 हजार चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे, इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज डाउनलोड कर लें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अदालत परिसर में नोटिस या चालान का प्रिंट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. ऐसे में लोगों को पहले से ही पोर्टल से डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट साथ लाना होगा, ताकि सुनवाई के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और ने नागरिकों से अपील की है कि जिनके ट्रैफिक चालान या नोटिस लंबित हैं, वे 22 मार्च को आयोजित होने वाली 'नेशनल लोक अदालत' का लाभ उठाएं. इससे न केवल पुराने मामलों का जल्द समाधान होगा बल्कि लोगों को कानूनी प्रक्रिया से राहत भी मिलेगी.

रोहिणी में उबर चालक ने महिला से की छेड़छाड़, शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार; 14 दिन की न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली । उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी में उबर बाइक टैक्सी से सफर कर रही महिला से चालक ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी चालक दिल्ली के बादली निवासी सचिन (34) को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी सचिन दिल्ली के बादली गांव का निवासी है। उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। पुलिस के अनुसार घटना 12 मार्च की है। महिला ने मोबाइल एप के जरिये रोहिणी सेक्टर-15 से पीतमपुरा जाने के लिए उबर बाइक टैक्सी बुक की थी। सफर के दौरान चालक ने महिला के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। महिला ने जब उसके व्यवहार पर आपत्ति जताई तो आरोपी ने उसे चुप रहने और शोर न मचाने की धमकी दी। बाद में चालक महिला को पीतमपुरा के एफ्यू ब्लॉक के पास छोड़कर चला गया। इसके बाद पीड़िता ने केएनके मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार आरोपी दसवीं पास है और पिछले एक साल से एप आधारित बाइक टैक्सी चालक के रूप में काम कर रहा था। सचिन पर साल 2011 में समयपुर बादली थाने में अपनी पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था।

सावधान दिल्ली! एलपीजी-पीएनजी कनेक्शन कटने का डर दिखाकर ठगी, पुलिस ने जारी की खास चेतावनी

नई दिल्ली । मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर सिर्फ वैश्विक तेल और गैस बाजार तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब इसका फायदा साइबर अपराधी भी उठाने लगे हैं. भारत में गैस सप्लाई को लेकर लोगों की चिंता के बीच ठग नए तरीके अपनाकर एलपीजी सिलेंडर जल्दी दिलाने या पीएनजी कनेक्शन कटने का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं.

दिल्ली पुलिस ने इस तरह की ठगी को लेकर विशेष चेतावनी जारी की है. ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है. इसका असर भारत में भी महसूस किया जा रहा है. हालांकि आम लोगों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए तेल कंपनियों ने सिलेंडर बुकिंग से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए हैं. गैस सप्लाई को लेकर फैली चिंता के बीच साइबर अपराधियों ने भी नया जाल बिछा दिया है. ठग सोशल मीडिया पोस्ट, फर्जी विज्ञापन और फोन कॉल के जरिए लोगों को झांसा दे रहे हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन कॉल्स में लोगों को जल्दी गैस सिलेंडर दिलाने या पीएनजी कनेक्शन बंद होने का डर दिखाया जा रहा है. एडिशनल कमिश्नर राजीव रंजन ने बताया कि, कई मामलों में ठग खुद को गैस एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर फोन करते हैं. वे पूछते हैं कि क्या आपने अपना एलपीजी सिलेंडर बुक कराया है. जब सामने वाला व्यक्ति

हैरानी जताता है तो कॉल करने वाला दावा करता है कि ईरान में युद्ध के कारण भारत में पेट्रोल और एलपीजी की भारी कमी आने वाली है. इसके बाद ठग कहते हैं कि अगर तुरंत बुकिंग नहीं कराई गई तो आपके कोटे का सिलेंडर किसी और को दे दिया जाएगा. इस बहाने वे बैंक से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं और एक लिंक भेजते हैं. जैसे ही व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, फोन तक रिमोट एक्सेस लेकर ठग बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कई लोगों को वॉट्सऐप और स्क्र के जरिए Pay Now, Get Gas Tomorrow जैसे मैसेज भी भेजे जा रहे हैं. इसमें जल्दी गैस डिलिवरी का लालच देकर एडवांस पेमेंट मांगा जाता है. गैस कंपनियों ने साफ किया है कि उनकी ओर से बुकिंग के समय इस तरह की कोई मांग नहीं की जाती है. साइबर ठग फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर गैस कंपनियों के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर नकली विज्ञापन भी चला रहे हैं. कई मामलों में लोगों को यह कहकर भी डराया जा रहा है कि बिल जमा नहीं करने पर उनका पीएनजी कनेक्शन काट दिया जाएगा. इस तरह के मैसेज के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि गैस बुकिंग हमेशा कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत ऐप के जरिए ही करनी चाहिए. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और संदिग्ध वेबसाइट पर पेमेंट डिटेल्स बिल्कुल न भरें. इसके अलावा किसी के कहने पर ओटीपी या बैंक से जुड़ी जानकारी साझा करना भी जोखिम भरा हो सकता है. अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसे तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए. इसके साथ ही सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना भी जरूरी है, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और नुकसान कम किया जा सके.

बिहार!

''मेरा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक से है। नीतीश जी हमारे संगठन से नहीं हैं। लेकिन त्याग, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण के मामले में वह हमसे से कहीं आगे हैं।'' बिहार के एक दलित भारतीय जनता पार्टी विधायक ने कहा। लेकिन अन्य विचार भी हैं। ''हम नीतीश जी की प्रशंसा करते हैं। लेकिन हम बिहार में आधुनिकीकरण और विकास भी चाहते हैं। जब भी हम औद्योगीकरण और भूमि के मुद्दे पर चर्चा करते, वह हमेशा हमें रोकते थे। उनका हमेशा यही कहना होता था-अगर किसान से जमीन छीन ली जाए, तो वह अपना जीवन यापन कैसे करेगा? अगर बिहार शहरीकरण में भारत के सबसे निचले 3 राज्यों में से एक है, तो इसका दोष उन्हीं पर जाता है। यह बेहद निराशाजनक था।'' बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री और अब भाजपा के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बताया। अब जबकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने अंतिम दिनों में हैं, राज्य के समीकरण से बाहर हो चुके हैं और भाजपा विधानसभा की 243 सीटों में से 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार में प्राथमिक निर्णय लेने वाली होगी, यह विचार करना उचित है कि आने वाले वर्षों में बिहार का स्वरूप कैसा हो सकता है और क्या राज्य के विकास के प्रति श्री कुमार का दृष्टिकोण भाजपा द्वारा साझा किया जाएगा? तथ्यों से इंकार नहीं किया जा सकता। नीति आयोग (2025) और बिहार सरकार (आर्थिक सर्वेक्षण, 2025) के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 2022-23 तक, कामकाजी आबादी, बिहार में जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन (49.6 प्रतिशत), सेवा क्षेत्र (28.9 प्रतिशत) और निर्माण क्षेत्र (18.4 प्रतिशत) में केंद्रित था। विनिर्माण क्षेत्र में केवल 5.7 प्रतिशत लोग कार्यरत थे। राज्य के लिए राहत की बात यह हो सकती है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर अवसंरचना निवेश किया है-केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राजमार्ग उन्नयन में 33,000 करोड़ रुपए, रेल क्षमता परियोजनाओं में 1 ट्रिलियन रुपए, और जिला सड़कों में सुधार आदि। दुविधा यह है कि बिहार को इस सारी अवसंरचना का क्या करना चाहिए? क्या उसे औद्योगिक निवेश में तेजी लानी चाहिए, जिसके लिए व्यापक (और महंगी) भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी और जिससे केवल नाममात्र का अतिरिक्त रोजगार ही मिलेगा? या फिर उसे औद्योगिक संपदाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिनमें लघु और मध्यम इकाइयां स्थापित की जा सकें, जैसे कि हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र। कृषि के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) सबसे अधिक रोजगार सृजित करते हैं। बिहार की सभी औद्योगिक इकाइयों में से 95 प्रतिशत और विनिर्माण उत्पादन का 65 प्रतिशत लघु एवं मध्यम उद्यमों से आता है। 2023 में जब जनता दल (यूनाइटेड), या जद (यू) फिर से राष्ट्रीय जनता दल का सहयोगी बना, बिहार के उद्योग विभाग ने एक रणनीतिक व्यापार योजना के साथ केंद्र से जोरदार अपील की, जिसमें उसने उन्हें दिया कि ऋण तक पहुंच और बाजार संपर्क एम.एस.एम.ई. के लिए 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अधिकारियों का कहना है कि मदद की गुहार पर मिली प्रतिक्रिया उम्मीदों से कम रही। मुख्यमंत्री के गठबंधन सहयोगी गलत तरह के थे। जब सहयोगी बदले, तो भाजपा के नीतीश मिश्रा, जिन्हें राज्य के उद्योग जगत का रक्षक माना जाता था, को मंत्री बनाया गया। हालांकि, 2025 में नीतीश कुमार की सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं रही, क्योंकि भाजपा ने जातिगत समीकरणों के आगे घुटने टेक दिए। उसने मधुबनी के एक ब्राह्मण को अपनी सूची से हटाने का विकल्प चुना। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि यदि भाजपा बिहार में औद्योगीकरण और शहरीकरण को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ना चाहती है, तो उसके समर्थकों और पैरोकारों का एक ही सामाजिक आधार से होना आवश्यक है। भाजपा के लिए यह एक अनिवार्य विकल्प है। राज्य सरकार की जाति जनगणना का उसका विरोध स्वयं ही सब कुछ बयां करता है। और फिर, दूसरा विकल्प भी है, जो अपने आप में बेहद समस्याग्रस्त है। 2022 में, जब भाजपा और जद (यू) सहयोगी थे, तब नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से भाजपा के उस आह्वान को ठुकरा दिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में लागू योगी आदित्यनाथ मॉडल का अनुसरण करने और मस्जिदों से सभी लाऊडस्पीकर हटाने की बात कही गई थी। ''इस बेतुकी बात को छोड़ दें। बिहार में हम किसी भी व्यक्ति के धार्मिक रीति-रिवाजों में दखल नहीं देते। बिहार के हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है।'' उन्होंने पूर्णिया में भाजपा सहयोगी शाहनवाज हुसैन के साथ एक जनसभा में कहा। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। भाजपा के पुराने नेता ऐसे कई मौकों को याद करते हैं, जब उन्होंने भाजपा के सहयोगी रहते हुए भी उसका डटकर मुकाबला किया। साथ ही, उन्होंने भाजपा के वक्फ कानून का समर्थन किया और मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन(एस.आई.आर.) पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। उनकी पार्टी ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़े और मुस्लिम वोटों का क्रमशः 6 प्रतिशत और 12 प्रतिशत हासिल किया। आंकड़े बताते हैं कि जब तक भाजपा के साथ जद (यू) है, वह मुस्लिम वोटों का भरपूर लाभ उठा सकती है। यह कहना मुश्किल है कि अगर कुमार सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो क्या स्थिति वैसी ही रहेगी। तो अहम सवाल यह है-उनकी अनुपस्थिति में क्या भाजपा जद (यू) की तरह हो जाएगी? या जद (यू) भाजपा की तरह हो जाएगी? विपक्ष भी खुद से यही सवाल पूछ रहा है।

गरीब घरों के बच्चे बन रहे कलैक्टर

यूपीएससी परीक्षा में गरीब और अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से आने वाले कई अभ्यर्थी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और स्मार्ट अध्ययन के दम पर सफलता हासिल कर के प्रतिभाशाली बन रहे हैं। ऑटो ड्राइवर के बेटे, मजदूर के बच्चे और ग्रामीण इलाकों के युवा बिना कोचिंग या सीमित डिग्री के आईएएस/आईपीएस बनकर निकले, इससे साबित होता है कि आर्थिक तंगी के सपने की राह में कोई बाधा नहीं है। इन सबकी सफलता से यह सिद्ध होता है कि नौकरी के लिए धन की नहीं, बल्कि योग्यता, परिश्रम और सही दिशा में निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत और लगन से कामयाब इन युवाओं में कई गरीब और ग्रामीण परिवारों से जुड़े हैं।

इससे साफ है कि कई गरीब मां-बाप के बच्चे आगे चलकर कलेक्टर (डीएम) और कप्तान (एसपी) बनेंगे।हर वर्ष आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनने का ख्वाब संजोने वाले लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को देश की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा माना जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय व्यापार सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों (प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार) में आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मैरिट लिस्ट जारी होती है। शिखा उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की रहने वाली है। उनके पिता प्रेमचंद, गांधी कन्या इंटर कॉलेज सियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। पिता भले ही चपरासी हों लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई को सपोर्ट किया। वहीं यूपीएससी में सफलता हासिल करके शिखा ने भी अपने पिता की मेहनत को बेकार नहीं होने दिया। पहले प्रयास में शिखा असफल हो गई। इससे निराश होकर उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और न खुद को कमजोर होने दिया। दूसरे प्रयास में शिखा ने यूपीएससी परीक्षा में एआईआर 113वीं रैंक के साथ सफलता हासिल कर ली। शिखा पांच भाई-बहन हैं, वे तीसरे नंबर पर हैं। मेरठ जिले में सरधना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में किसान परिवार के हर्ष नेहरा की 74वीं रैंक आई है। हर्ष नेहरा की मां अनीता टीचर हैं। पिता किसान हैं। हर्ष घर का बड़ा बेटा है। मां अनीता का कहना है कि मैं और उसके पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन इंटर पास करने के बाद वह आईएएस बनने की जिद करने लगा। बिहार के नवादा जिले के हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत पांचू निवासी रितिका पांडेय ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 185वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। सीमित संसाधनों के बीच कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। रितिका पांडेय के पिता संजय पांडेय मूल रूप से हिसुआ पांचू के निवासी हैं और साधारण व्यवसाय करते हैं। वे दुकानों में कैरी बैग की आपूर्ति करने का काम करते हैं लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना उनका सपना और जुनून रहा है। पिता के इसी संघर्ष और लगन को रितिका ने अपने जीवन की प्रेरणा बनाया। रितिका ने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। पहले प्रयास में वे प्रारंभिक परीक्षा तक पहुंची थीं, जबकि दूसरे प्रयास में उन्होंने साक्षात्कार तक का सफर तय किया था लेकिन अंतिम परिणाम में उनका चयन नहीं हो सका था। तीसरे प्रयास में उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः सफलता हासिल कर ली। बुलंदशहर जिले के निवासी किसान के बेटे विपिन चौधरी ने 538वीं रैंक हासिल की। 2017 में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में विपिन ने जिले में टॉप किया था। पूरे डिवीजन में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। 21 जून 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें लखनऊ में सम्मानित किया था। इसी तरह रायबरेली के एक छोटे से गांव चंदिमऊ से निकलकर देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी फतह करने वाले विमल कुमार की कहानी संघर्ष और अटूट संकल्प की एक अद्भुत मिसाल है। ईंट भट्ठों और खेतों के बीच पले-बढ़े विमल के पिता ने गरीबी और अभावों के बीच मजदूरी कर अपने बेटे को पढ़ाया। विमल ने अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर न केवल नवोदय विद्यालय में जगह बनाई, बल्कि आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की लेकिन देश सेवा का जज्बा ऐसा था कि उन्होंने कैंपस सिलेक्शन ठुकराकर आईएएस बनने का रास्ता चुना। अपने दृढ़ निश्चय और कड़े परिश्रम से विमल ने यूपीएससी में 107वीं रैंक हासिल की और आज वे एक मिसाल बनकर उभरे हैं। सफलता के लिए एक कीमत अदा करनी होती है। संघर्ष करना होता है। कुर्बानियां देनी होती हैं। कोई मजदूर का बेटा है तो किसी के घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वह इस परीक्षा की तैयारी कर सके लेकिन कहते हैं न सोना तपकर ही 'कुंदन' बनता है। तो इस परीक्षा में भी ऐसे कई कुंदन निकले हैं। सिविल सेवकों को प्रशासनिक सेवा की रीढ़ माना जाता है लेकिन काफी समय से सिविल सेवकों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठे हैं। नौकरशाहों के साथ नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते ही रहते हैं लेकिन यह ध्यान रहे कि भ्रष्ट सिविल सेवक निष्ठावान सिविल सेवकों की बदनामी कारण बनते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि भ्रष्ट सिविल सेवकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और अपना काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए।

सम्पादकीय...

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

देश के अनेक राज्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के ज्ञान और इस्तेमाल को उच्च शिक्षा के छात्रों के सिलेबस में शामिल किया जा रहा है, यह एक अच्छी पहल है। आज उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जो शिक्षण, सीखने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक स्मार्ट और सक्षम बना रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने वाला एक सहायक औजार बन गई है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्र की सीखने की गति और शैली को समझकर पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर सकती है। यह पिछड़े छात्रों की पहचान करने और उनके लिए विशेष ट्यूटोरियल प्रदान करने में मदद करती है। चैटबॉट और वर्चुअल ट्यूटर छात्रों को 24×7 सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उनके सवालों के तुरंत जवाब मिल जाते हैं और वे अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं। परीक्षा, ग्रेडिंग और अन्य प्रशासनिक कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग समय और संसाधनों की बचत करता है, जिससे शिक्षक अपना ध्यान पढ़ाने और शोध पर लगा पाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े टूल डाटा का विश्लेषण करने, जटिल पैटर्न की पहचान करने और शोध पत्रों के सारांश तैयार करने में शोधकर्ताओं की मदद करते हैं, जो अकादमिक अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। ए.आई.-आधारित टूल्स (जैसे टैक्स्ट-टू-स्पीच और रीयल-टाइम अनुवाद) दिव्यांग छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री को सुलभ बनाकर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उन छात्रों की पहचान पहले ही की जा सकती है, जो पढ़ाई में पीछे रह रहे हैं या जिनका स्कूल छोड़ने का जोखिम है, जिससे समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। डाटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, तो यह अनुचित निर्णय ले सकता है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज एक शक्तिशाली उपकरण है, जो सही तरीके से उपयोग किए जाने पर सीखने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। हालांकि, इसे लागू करते समय नैतिक मानकों और मानवीय हस्तक्षेप को बनाए रखना आवश्यक है। उच्च शिक्षा में शिक्षकों और छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (ए.आई.) महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी तकनीकों का उपयोग छात्रों के लिए बिना किसी सीमा के सीखने के अधिक लचीले समाधानों को बढ़ावा देता है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से दुनिया भर के विश्वविद्यालय बढ़े हुए लचीलेपन और गति के कारण अधिक संख्या में छात्रों का नामांकन कर रहे हैं। विकसित देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया है, जबकि विकासशील देश आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के कार्यान्वयन के मामले में विकसित देशों की तुलना में अभी भी प्रारंभिक चरण में हैं। इसलिए, उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोगिता से संबंधित इस अंतर को कम करने के लिए इसको अपनाने की आवश्यकता है। आज कमजोर बुनियादी ढांचा, सूचना तक खराब पहुंच, संस्थानों से समर्थन की कमी, आवश्यक संसाधनों की अपर्याप्तता और खराब तकनीकी कौशल इत्यादि, ये सभी विकासशील देशों के लिए विभिन्न बाधाएं हैं।

युद्ध तय नहीं करते कि कौन सही है- राष्ट्रों की ताकत या नैतिकता, जंग के दौर में मानवता का सवाल

क्या यह दुनिया सिर्फ बम और बाजार से ही संचालित होगी? हमें सोचना होगा कि इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए? एक तरफ एआई, दूसरी तरफ युद्ध में बरसते ड्रोन, आखिर मनुष्य जाए तो कहां जाए? गांधी जी तो दंगों के समय नोआखाली पहुंच गए थे। आखिर हम कहां पहुंचें। फिर से अहिंसा की आवाज उठेगी क्या? क्या कलिंग युद्ध से कोई महान अशोक बनकर लौटेगा, क्या? वे बच्चे जो बड़े भी न हो सके, वे जरूर पूछेंगे कि आखिरकार तेल के कुएं, जलियांवाला बाग का कुआं और वह ठाकुर का कुआं इतना गहरा और निर्मम क्यों रहा कि कभी इन सबका मन मनुष्यता के लिए नहीं पसीजा। उन धमाकों के बाद, जो शहर या गांव बचेंगे, उनको कौन संभालेगा? अंत में बर्टेंड रसेल हमें याद दिलाते है कि युद्ध यह तय नहीं करता कि कौन सही है, वह सिर्फ यह तय करता है कि कौन बचा है! इसलिए समय आ गया है कि इस दुनिया को अहिंसा के नायकों का नेतृत्व मिले और शांति के इतिहास को आवाज भी दी जाए। यह इन्सानियत की ओर वापसी होगी, उस आध्यात्मिक पुकार के साथ जो इस बार 'सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ वर्ल्ड' होगा।

कोविड से बची दुनिया मानो यह मान बैठी है कि युद्ध करना और बम गिराना ही किसी राष्ट्र की पहचान है। नहीं तो फेफड़ों को बचाती और वैक्सीन ढूंढती उन भयभीत धड़कनों के बारे में सोचिए, जिन्हें अगले पल का पता नहीं था, फिर भी सभी, इनको-उनको बचाने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जितनी यह दुनिया इनकी है, उतनी उनकी भी है। लेकिन पता नहीं फिर से मानो इस पृथ्वी को नजर लग गई। अब बस अकड़ देखिए, उन मुल्कों की, जहां सिर्फ और सिर्फ तेल के कुएं हथियाने और बम गिराने की प्रतियोगिता चल रही है। नैतिकता का प्रश्न, उस शांति का भाव, किसी और ग्रह का मालूम हो रहा है। हम सब देख रहे हैं और यह भी मान रहे हैं कि दुनिया धीरे-धीरे तीसरे विश्वयुद्ध की ओर बढ़ रही है। ऐसे में, सबसे जरूरी सवाल यह होगा कि युद्ध से कैसे बचा जा सकता है और शांति के मूल्यों को दोहराने के लिए दुनिया को क्या करने की जरूरत है। कई संघर्ष चल रहे हैं, जैसे ड्रोन कंट्रोल्ड युद्ध या साइबर हमले, वगैरह। क्या पैसे और बम जैसी धमकियों के जरिये देशों पर दबाव डालना सही है? क्या सबसे ताकतवर देश के तौर पर आम लोगों को मारने वाले ड्रोन का इस्तेमाल 'कोलैटरल डैमेज' के तौर पर करना या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना नैतिक है? युद्ध को अपनी पहचान समझाने के लिए मूल्यों या नैतिकता की जरूरत नहीं होती। यह शांति के मूल्य ही हैं, जो युद्ध की दुनिया को चुनौती देते हैं। शांति सिर्फ एकजुटता और संवेदनशीलता से आती है। इसे वैश्विक स्तर पर बनाने और फैलाने के लिए लीडरशिप की हर तरह की सोच में नैतिकता की भावना की जरूरत होती है। परमाणु बम या दूसरे तरह के परमाणु परीक्षण का जलवायु परिवर्तन पर क्या असर होगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसराइल और फलस्तीन में हजारों युवा, बच्चे, औरतें-मर्द मारे गए और रूस तथा यूक्रेन में भी यही नजीने हुए। अब अमेरिका व ईरान के साथ-साथ पश्चिम एशिया में गोले बरसाता यह युद्ध क्या उन बच्चों से माफी मांग पाएगा, जो मारे गए। जो बच गए या बचेंगे उनकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक दिक्कतों का क्या? आखिरकार, वे शांति के दूत कहां हैं? क्या महात्मा गांधी, विवेकानंद ने कभी सोचा होगा कि एक इन्सान का अहंकार या घमंड और जिद लाखों हजारों लोगों को मौत की तरफ खींच लेगा, खासकर युद्ध व अनगिनत मौतें मानो एक सामान्य बात बन जाएगी? एक बार जब महात्मा गांधी से किसी पत्रकार ने यह पूछा कि अगर कोई हवाई जहाज से बम गिर जाए, तो वह क्या करेंगे? गांधी जी का जवाब था कि वह उस पायलट के बारे में सोचेंगे, जो बम गिराते वक्त कितना परेशान रहा होगा। अगर आज विवेकानंद होते, तो वह कह जाते कि विश्व के नागरिकों के हित में महान अमेरिका वह होगा, जो युद्ध नहीं, शांति का नेतृत्व करेगा, जो आने वाली नस्लों को जीवन की क्षणभंगुरता नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता और प्रयोजन का अर्थ समझाएगा और उन्हें भी अपने 'मैं' से मुक्त होना सिखाएगा। आज अगर स्वामी विवेकानंद होते, तो वह बहुत चिंतित होते और फिर वह प्रश्न भी पूछते कि आखिर किसी राष्ट्र की अस्मिता क्या होती है? नेतृत्व शक्ति का केंद्र होता है या महान नैतिक मूल्यों का? किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा क्या है? ऐसी दुनिया में एक नागरिक का सम्मान क्या होता है, जहां इन्सानी रिश्ते व्यापारिक फायदों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जहां किसी देश की महानता को आसानी से तात्कालिक स्वार्थों से बदल दिया जाता है, जहां संस्थाएं कंकड़-पत्थरों को तो चमकाती हैं, लेकिन वे चुपचाप हीरों की चमक फीकी कर देती हैं, जहां देशों के रिश्ते रोज नए दुश्मनों के नाम पर बदल रहे हैं... जहां व्यापार के नाम पर, तेल के भंडार के नाम पर, टैरिफ के नाम पर, और आगे ड्रोन, मिसाइलों, लड़ाकू विमानों के नाम पर, तानाशाही के नाम पर, आतंकवाद, डर और हिंसा के नाम पर दो राष्ट्रों के रिश्ते परिभाषित हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से, ईरान से, सभी से पूछते, और फिर पूरी दुनिया से पूछते। उन तमाम नेतृत्व से पूछते, जिन के लिए जनता एक ग्राहक है और देश बाजार। उस हर युवा से पूछते, जो देश और समाज से ज्यादा अपनी धुन में डूबा है? अपने ज्ञान और शख्सियत से जिस विवेकानंद ने अमेरिका को मनुष्यता, राष्ट्रवाद, अध्यात्म और जीवन का उद्देश्य सिखाया, उसके लिए अमेरिका और यहां तक कि दुनिया की लीडरशिप को भी स्वामी विवेकानंद को फिर से फॉलो करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसके लिए कोई टैरिफ नहीं लगेगा और इसमें कोई आर्थिक हित या व्यापार भी शामिल नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता काफी हद तक नेताओं की नैतिक सोच और मूल्यों पर भी निर्भर करती है। क्या संसार के नेतृत्वकर्ता, युद्ध से पहले और उसके दौरान इन्सानियत का भविष्य शांति के नजरिये से देखना चाहते हैं? क्या गांधी, लिंकन या विवेकानंद ने कभी सोचा होगा कि हिटलर के बाद फिर कोई घृणा की हवा ऐसी चलेगी, जो तमाम नेतृत्व के घमंड और जिद की खातिर लाखों लोगों को कब्र की ओर खींच सकती है। और फिर शांति के लिए यूएनओ की क्या भूमिका है? पिछले दशक से वह ज्यादातर समय चुप या निष्क्रिय क्यों रहना पसंद कर रहा है? क्या संसार के लीडर्स कंसोर्टियम ऑफ पीस नहीं बना सकते? आखिर दुनिया अगर बम से ही संचालित होनी है, तो फिर उन तेल के कुओं का क्या होगा? आखिर जीने के लिए तो हवा, पानी और मूल्यों से लैस दुनिया चाहिए। क्या शांति के मूल्य को लेकर चलने वाला अब कोई नेतृत्व नहीं आएगा क्या?

क्या यह दुनिया सिर्फ बम और बाजार से ही संचालित होगी? हमें सोचना होगा कि इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए? एक तरफ एआई, दूसरी तरफ युद्ध में बरसते ड्रोन, आखिर मनुष्य जाए तो कहां जाए? गांधी जी तो दंगों के समय नोआखाली पहुंच गए थे। आखिर हम कहां पहुंचें। फिर से अहिंसा की आवाज उठेगी क्या? क्या कलिंग युद्ध से कोई महान अशोक बनकर लौटेगा, क्या? वे बच्चे जो बड़े भी न हो सके, वे जरूर पूछेंगे कि आखिरकार तेल के कुएं, जलियांवाला बाग का कुआं और वह ठाकुर का कुआं इतना गहरा और निर्मम क्यों रहा कि कभी इन सबका मन मनुष्यता के लिए नहीं पसीजा। उन धमाकों के बाद, जो शहर या गांव बचेंगे, उनको कौन संभालेगा? अंत में बर्टेंड रसेल हमें याद दिलाते है कि युद्ध यह तय नहीं करता कि कौन सही है, वह सिर्फ यह तय करता है कि कौन बचा है! इसलिए समय आ गया है कि इस दुनिया को अहिंसा के नायकों का नेतृत्व मिले और शांति के इतिहास को आवाज भी दी जाए। यह इन्सानियत की ओर वापसी होगी, उस आध्यात्मिक पुकार के साथ जो इस बार 'सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ वर्ल्ड' होगा।

इच्छा मृत्यु केवल कानून ही नहीं, मानवीय गरिमा का प्रश्न

भारतीय समाज में यह गहरी धारणा रही है कि परिवार के किसी सदस्य की सेवा तब तक की जाए, जब तक उसके प्राण स्वाभाविक रूप से समाप्त न हो जाएं। जीवन की रक्षा और उसकी देखभाल को एक नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता रहा है। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में रोगी की सेवा केवल चिकित्सा का विषय नहीं होती, बल्कि भावनात्मक, धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से भी जुड़ी होती है। कई बार यह भी देखा गया है कि प्रियजन की मृत्यु के बाद भी उसे लंबे समय तक जीवन लौटने की आशा में संभालकर रखा जाता रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, जहां से सामान्य जीवन में लौटने की कोई संभावना न हो और उसका अस्तित्व केवल कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणालियों पर निर्भर रह जाए, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या केवल जैविक अस्तित्व को बनाए रखना ही जीवन की रक्षा है? या फिर जीवन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को पीड़ा से मुक्ति देने का अधिकार भी स्वीकार किया जाना चाहिए? इसी जटिल और संवेदनशील प्रश्न के केंद्र में 11 मार्च 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया वह निर्णय है, जिसमें गाजियाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी गई। लगभग तेरह वर्षों से कोमा में जीवन बिताने वाले इस युवक के मामले में अदालत का यह निर्णय केवल एक कानूनी आदेश भर नहीं है, बल्कि जीवन, मृत्यु और मानवीय गरिमा के बीच संतुलन खोजने का एक गंभीर एवं संवेदनशील प्रयास भी है। दरअसल, हरीश राणा का मामला हमें यह सोचने के लिए बाध्य करता है कि इच्छामृत्यु का प्रश्न केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि एक गहरी मानवीय कहानी भी है। यह एक ऐसे युवा की कहानी है, जिसका जीवन एक दुर्घटना के बाद अचानक बदल गया और जो तेरह वर्षों तक एक मौन जीवन-मृत्यु संघर्ष में जीता रहा। उस संघर्ष में शब्द नहीं थे, संवाद नहीं था, केवल एक स्थिर और असहाय जैविक अस्तित्व था। ऐसे में परिवार, चिकित्सकों और समाज के सामने यह कठिन दुविधा खड़ी हो जाती है कि जीवन को किस सीमा तक कृत्रिम रूप से बनाए रखा जाए। इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। समय के साथ न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद की व्याख्या को व्यापक बनाते हुए यह स्पष्ट किया कि जीवन का अधिकार केवल सांस लेने या जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी है। इसी संवैधानिक दृष्टिकोण ने आगे चलकर यह प्रश्न उठाया कि यदि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, तो क्या उसे गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी नहीं होना चाहिए? भारत में इच्छामृत्यु से जुड़ा न्यायिक विमर्श धीरे-धीरे विकसित हुआ है। वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी। यह मामला एक ऐसी नर्स का था, जो दशकों तक कोमा की स्थिति में रही। उस निर्णय ने इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। इसके बाद वर्ष 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को संवैधानिक मान्यता देते हुए 'लिविंग विल' की अवधारणा को स्वीकार किया। इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही यह लिखित रूप में व्यक्त कर सकता है कि यदि वह असाध्य स्थिति में पहुंच जाए तो उसे कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणालियों पर निर्भर न रखा जाए। हरीश राणा के मामले में चिकित्सा विशेषज्ञों के बोर्ड ने यह स्पष्ट किया कि निरंतर उपचार का कोई चिकित्सीय उद्देश्य शेष नहीं रह गया था। चिकित्सा केवल जैविक अस्तित्व को लंबा खींचने का माध्यम बन गई थी। ऐसे में अदालत की स्वीकृति इस कठिन सत्य को स्वीकार करती है कि जीवन की गरिमा केवल जीने में ही नहीं, बल्कि मृत्यु में भी बनी रहनी चाहिए। फिर भी इच्छामृत्यु का प्रश्न अत्यंत जटिल और विवादास्पद रहा है। दुनिया के अनेक देशों में इस विषय पर गंभीर नैतिक और कानूनी बहस चलती रही है। कई देशों ने इसे सीमित परिस्थितियों में कानूनी मान्यता दी है, जबकि कई अन्य देशों में इसके दुरुपयोग की आशंका के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में भी यह विषय संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि यहां पारिवारिक संबंधों, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक भावनाओं की भूमिका अत्यंत गहरी है। इसी संदर्भ में जैन धर्म में प्रचलित संथारा या सल्लेखना की परंपरा भी कई बार चर्चा में आती रही है। जैन दर्शन में इसे मृत्यु का महोत्सव कहा गया है। संथारा का अर्थ है-जीवन के अंतिम चरण में धीरे-धीरे आहार और शरीर की आसक्तियों का त्याग करते हुए शांति एवं समाधिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना। जैन आचार विचार में इसे आत्मसंयम और आध्यात्मिक साधना का सर्वोच्च रूप माना गया है। संथारा और आधुनिक इच्छामृत्यु के बीच अंतर भी है और समानताएं भी। संथारा का आधार आध्यात्मिक साधना और वैराग्य है, जबकि आधुनिक इच्छामृत्यु का आधार चिकित्सा विज्ञान और मानवीय पीड़ा से मुक्ति का विचार है। फिर भी दोनों के केंद्र में एक समान भाव दिखाई देता है-जीवन की अंतिम अवस्था में गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान। हालांकि इस परंपरा को लेकर भी न्यायालयों में बहस होती रही है कि क्या इसे धार्मिक स्वतंत्रता माना जाए या आत्महत्या के रूप में देखा जाए। इस बहस ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन और मृत्यु से जुड़े प्रश्न केवल कानूनी तर्कों से हल नहीं होते, बल्कि उनमें नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयाम भी शामिल होते हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक विनोबा भावे ने इस परंपरा की विशेष सराहना की थी। उन्होंने कई अवसरों पर यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि यदि संभव हो तो वे भी जीवन के अंतिम क्षणों में इसी प्रकार की शांत, संयमित और जागरूक मृत्यु प्राप्त करना चाहेंगे। इसीलिए हरीश राणा का मामला हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि संविधान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संवेदनशील व्याख्या में निहित है। जब न्यायपालिका जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए मानवीय गरिमा और करुणा को केंद्र में रखती है, तब वह केवल कानून का पालन नहीं करती, बल्कि समाज को अधिक संवेदनशील और मानवीय दिशा भी प्रदान करती है। यह भी सच है कि भारत में इच्छामृत्यु को लेकर अभी तक कोई समग्र और स्पष्ट कानून नहीं है। न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद परिवारों और चिकित्सकों को कई बार जटिल प्रक्रियाओं और कानूनी आशंकाओं का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं इस विषय पर एक व्यापक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया है। ऐसा कानून बनाते समय दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, यह कि असाध्य रोगियों को अनावश्यक पीड़ा से मुक्ति मिल सके। दूसरी, यह कि किसी प्रकार के दबाव, स्वार्थ या आर्थिक कारणों से किसी व्यक्ति को इच्छामृत्यु के लिए विवश न किया जा सके। स्पष्ट प्रोटोकॉल, पारदर्शी चिकित्सा मूल्यांकन और रोगी की स्वायत्त इच्छा का सम्मान इस प्रक्रिया के आवश्यक तत्व होने चाहिए। निश्चिततौर पर यह कहा जा सकता है कि हरीश राणा के मामले में दिया गया निर्णय केवल एक न्यायिक आदेश नहीं है, बल्कि संवैधानिक करुणा का एक उदाहरण है। इसमें न्याय, संवेदना और मानवीय गरिमा तीनों का संतुलित रूप दिखाई देता है। वास्तव में यह निर्णय हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन का सम्मान केवल उसे लंबा खींचने में नहीं, बल्कि उसकी गरिमा को बनाए रखने में है। जब उपचार असंभव हो जाए और चिकित्सा केवल पीड़ा को बढ़ाने का माध्यम बन जाए, तब गरिमापूर्ण विदाई भी मानवीयता का ही विस्तार बन जाती है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि भारत में इच्छामृत्यु के प्रश्न पर व्यापक सामाजिक संवाद हो और एक ऐसा संवेदनशील तथा संतुलित कानूनी ढांचा तैयार किया जाए, जो व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने और गरिमा के साथ मरने-छूटने का अधिकार सुनिश्चित कर सके।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पैमलवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

वसंतोत्सव में झूम उठा पडरौना, लोकगीत-लोकनृत्य और फूलों की होली में सराबोर हुआ माहौल

पडरौना,कुशीनगर।

विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था पडरौना,विश्व भोजपुरी सम्मेलन कुशीनगर, सिटी क्लब पडरौना, रेडियो प्रज्ञा 90.4 एफएम तथा श्री पिंजरापोल गौशाला के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को पडरौना-कसया मार्ग स्थित सोहरौना में डॉ. प्रणव श्रीवास्तव पुत्र डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव के नव निर्मित आवास परिसर में भव्य वसंतोत्सव एवं होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोक संस्कृति,साहित्य और संगीत का ऐसा संगम देखने को मिला कि पूरा परिसर बसंती उल्लास और रंगों के उत्सव में सराबोर हो उठा। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार अनूप मिश्रा ने प्रभावशाली ढंग से किया। कार्यक्रम का उद्घाटन खड्डा के विधायक विवेकानन्द पाण्डेय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वसंतोत्सव नवजीवन और उल्लास का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने का कार्य करते हैं। लोकगीत और लोक नृत्य हमारी लोक संस्कृति को सहेज

विधायक खड्ड विवेकानंद पांडेने उद्घाटन और जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर ने किया समापन

सोहरौना में आयोजित भव्य सांस्कृतिक आयोजन में कलाकारों ने बांधा समां, कवि सम्मेलन में गूंजी बसंत और होली की रचनाएं

कर अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं इनका संरक्षण संवर्धन हम सब का दायित्व है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि भोजपुरी भाषा और संस्कृति की समृद्ध परंपरा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों की बड़ी भूमिका है। वरिष्ठ भाजपा नेता नथुनी प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए कलाकारों और साहित्यकारों का योगदान अमूल्य है और समाज को उनका सम्मान करना चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम मुरली मनोहर मिश्र ने कहा कि साहित्य और संस्कृति समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं और इस तरह के कार्यक्रम सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय लोक गायक राम दरस शर्मा,राकेश श्रीवास्तव और फोक जलवा भारत के विजेता वीर सिंह सूफी और उपविजेता नीरज निराला ने अपने सुरों से समां बांध दिया। वहीं नाट्य संस्था संगम सलेमपुर के कलाकारों डिंपल श्रीवास्तव, प्रांजल श्रीवास्तव, अनुप्रिया चौहान, पलक गौड़ नृत्य निर्देशक श्रीमती शीलम राव टीम लीडर राधेश्याम गुप्ता ने आकर्षक लोकनृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वरिष्ठ कवि दिनेश भोजपुरिया एवं आकाश महेश पुरी की दमदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को और अधिक रंगारंग बना दिया। अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी गायक राकेश श्रीवास्तव एवं भोजपुरी प्रस्तुत शिवेंद्र पांडे के कार्यक्रम के दौरान फूलों की होली खेली गई और उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं दीं। पूरे परिसर में हंसी- खुशी,संगीत और रंगों का अनोखा माहौल देखने को मिला। इसके अलावा साक्षी गुप्ता, अनामिका गुप्ता, यशिका मौर्या,सुभाष सुहाना,मंटू पाठक धीरज राव,दिनेश पाठक सहित दर्जनों कलाकारों ने अपनी शानदार पारंपरिक प्रस्तुति दी जिससे पूरा सभागार झूम उठा। समारोह के समापन अवसर पर जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने कहा कि केवल भौतिक सामाजिक और आर्थिक विकास ही विकास का पैमाना नहीं है बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सहजते हुए आगे बढ़ना ही विकास है और जिस प्रकार एक पौधे के लिए उसकी जान मजबूत होना आवश्यक है वैसे अपनी लोक संस्कृति को बचाए रखना अपनी जड़ों से जुड़े रहने जैसा है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है और ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक सोच और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष आर. के. भट्ट 'बावरा', उपाध्यक्ष ज्ञानवर्धन गोविन्द राव तथा श्री पिंजरापोल गौशाला के मंत्री अखिलेश गोयल, सिटी क्लब के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने सभी अतिथियों,कलाकारों और आगंतुकों का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में रेडियो प्रज्ञा के प्रबंध निदेशक परशुराम श्रीवास्तव, संरक्षक,शैलेंद्र दत्त शुक्ल सहित बड़ी संख्या में साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। देर शाम तक लोकगीत, लोकनृत्य, कविता पाठ और होली मिलन के रंग में डूबा यह बसंतोत्सव क्षेत्रवासियों के लिए यादगार बन गया।

इस अवसर पर अमित वर्मा,संजीव गुप्ता, अमित पांडे, अनिल मिश्रा, घनंजय मिश्रा, बीएन मिश्रा,श्रीमती कालिंदी त्रिपाठी, डॉक्टर श्रीमती सुनीता पांडे,वरिष्ठ नेता विजय पांडे, सपा नेता शाहिद लारी,सीमा गुप्ता, पत्रकार दिनेश पांडे, आफताब आलम अंसारी,शंभू सजल, दिनेश पांडे, जगदंबा अग्रवाल,अजय सर्राफ, नवल किशोर त्रिपाठी, सागर पांडे, मोनिका खुशी,अमन,नूर, अशोक शुक्ला, संजय चाणक्य ज्योति भान मिश्रा,पवन मिश्रा, साजिद अंसारी, खुर्शेद आलम, मोहम्मद नईम, सौम्या जायसवाल, सीमा शुक्ला,नम्रता भट्ट,आदित्य श्रीवास्तव, दीपक मिश्रा,अजीत यादव,सागर पांडेय, अब्दुल मजीद,आदि सैकड़ो की संख्या में वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे।

असंगठित श्रमिकों को संविधान व 73वें-74वें संशोधन की दी गई जानकारी, दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित

पडरौना/कुशीनगर।

श्रमिक सुविधा केंद्र के तत्वावधान में असंगठित श्रमिकों को संवैधानिक अधिकारों और स्थानीय स्वशासन से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देने के उद्देश्य से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पडरौना स्थित होटल जी स्टार के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें जिले भर से सैकड़ों असंगठित श्रमिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला के प्रथम दिन 14 मार्च को प्रशिक्षक अधिवक्ता रवि सिंह ने भारतीय संविधान की परिभाषा, उसका महत्व, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार तथा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्य व दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार और

कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। इस दौरान प्रशिक्षक फातिमा बेग ने नागरिकों के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अधिकारों के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व भी है कि वह संविधान और कानून का सम्मान करते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। प्रशिक्षण के दूसरे दिन 15 मार्च को रामवृक्ष गिरि, आयोध्याल श्रीवास्तव तथा फातिमा बेग ने श्रमिकों को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया है, जिसमें 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के अधिकार और कार्य निर्धारित किए गए हैं। वहीं 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया, जिसमें 12वीं अनुसूची के माध्यम से नगर पालिकाओं के अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। प्रशिक्षकों ने कहा कि इन संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी होने से श्रमिक अपने अधिकारों और स्थानीय शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। कार्यशाला में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए असंगठित श्रमिक प्रतिनिधियों में अक्षयबर पासवान, जालंधर, सुनीता देवी, हरदेव प्रजापति, इंद्रावती देवी, घरभरन प्रसाद, विश्वनाथ यादव, आनंद खरवार, नम्रता देवी, खुशबू सिंह, रंभा, विश्वलकला और सुमन देवी सहित श्रमिक सुविधा केंद्र के सहयोगी दुर्गा, राजू प्रसाद, दिनेश प्रसाद और रामबहाल सिंह उपस्थित रहे।

भटनी में सुमित्रा इंडियन गैस एजेंसी ने शुरू की होम डिलीवरी

निर्धारित स्थानों पर भी जारी रहा गैस वितरण, उपभोक्ताओं को मिली राहत

भटनी देवरिया।

नगर क्षेत्र में रसोई गैस उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुमित्रा इंडियन गैस एजेंसी, भटनी द्वारा गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी गई है। एजेंसी के कर्मचारी उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर गैस सिलेंडर पहुंचाते हुए दिखाई दिए। साथ ही एजेंसी द्वारा नगर और आसपास के जिन स्थानों को गैस वितरण के लिए पहले से निर्धारित किया गया है, वहां पर भी सिलेंडर का वितरण किया गया। इन स्थानों पर भी उपभोक्ता पहुंचकर गैस लेते हुए दिखाई दिए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले गैस लेने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और कई बार गैस समय से नहीं मिल पाती थी। अब होम डिलीवरी शुरू होने से काफी हद तक सुविधा मिल जाएगा। वहीं कुछ उपभोक्ता घर पर ही गैस प्राप्त करते हुए भी दिखाई दिए। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि यह व्यवस्था नियमित रूप से चलती रही तो लोगों को काफी राहत मिलेगी और गैस वितरण व्यवस्था भी सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

साक्षरता की ओर बड़ा कदम- 650 केंद्रों पर 16 हजार असाक्षरों ने दी परीक्षा, अब मिलेगा एनआईओएस का प्रमाणपत्र

देवरिया।

शिक्षा की मुख्यधारा से कटे उन लोगों के लिए रविवार का दिन खास था, जो उम्र के इस पड़ाव पर किताब थामे परीक्षा देने बैठे। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जनपद के 650 परीक्षा केंद्रों पर एक साथ साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 16 हजार असाक्षरों ने हिस्सा लिया। यह परीक्षा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन लोगों के लिए थी, जिन्हें पिछले दिनों विशेष कक्षाओं के जरिए साक्षर बनाया गया। महीनों की मेहनत के बाद अब परीक्षा में बैठे इन प्रतिभागियों के चेहरे पर न सिर्फ उत्साह था, बल्कि एक नई पहचान पाने की ललक भी झलक रही थी।

प्रमाणपत्र मिलेगा तो मिलेगी औपचारिक मान्यता

यह परीक्षा इसलिए भी अहम है, क्योंकि मूल्यांकन के बाद सफल प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की ओर से साक्षरता प्रमाणपत्र दिया जाएगा। यह प्रमाणपत्र उन्हें समाज में साक्षर के रूप में औपचारिक पहचान दिलाएगा। किसी सरकारी फॉर्म में दस्तखत करने से लेकर छोटी-मोटी पढ़ाई-लिखाई के कामों में अब उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन, छूटे प्रतिभागियों को सितंबर में मिलेगा दूसरा मौका, बीएसए अनिल कुमार सिंह ने बालिकाओं को परीक्षा की तैयारी के दिए टिप्स

प्रशासनिक तैयारियां रहीं चाक-चौबंद

परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने पुख्ता इंतजाम किए थे। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को ब्लॉक स्तर का नोडल अधिकारी बनाया गया, वहीं जिला समन्वयकों को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीएसए अनिल कुमार सिंह और सदर विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी देव मुनि वर्मा ने सेंविलियन बैदा बांस पार सहित कई केंद्रों का दौरा कर परीक्षा का जायजा लिया। उन्होंने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अगर किसी कारणवश कोई प्रतिभागी आज की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया है, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। आगामी सितंबर 2026 में फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें ऐसे प्रतिभागियों को मौका दिया जाएगा।

कस्तूरबा विद्यालय का भी किया निरीक्षण

साक्षरता परीक्षा के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बैतालपुर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उनकी पढ़ाई-लिखाई और पाठ्यचर्या से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। विद्यालय में छात्राओं की अच्छी उपस्थिति मिली, जिस पर उन्होंने संतोष जताया। बीएसए ने बालिकाओं को आगामी वार्षिक परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह हथियार है, जो हर मुकाम हासिल करने में मददगार साबित होगी। गौरतलब है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत यह पहल प्रदेश स्तर पर साक्षर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। जनपद में इस कार्यक्रम की सफलता से यह उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में और अधिक लोग साक्षरता की मुख्यधारा से जुड़ेंगे।

गैस की कालाबाजारी के खिलाफ भरपटिया में बृहद चौपाल, प्रशासन को कार्रवाई की चेतावनी

पडरौना/कुशीनगर।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पडरौना ब्लॉक के भरपटिया ग्रामसभा में गैस की कालाबाजारी के विरोध में एक बृहद चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता पप्पू पांडे ने किया। चौपाल में ग्रामीणों ने गैस एजेंसियों की मनमानी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए जिला प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई करने की चेतावनी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पप्पू पांडे ने कहा कि वैश्विक संकट का हवाला देकर कुछ गैस संचालक कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध होने के बावजूद भी आम जनता को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन लगातार यह आश्वासन दे रहे हैं कि आमजन की सुविधा के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी कई गैस संचालक सिलेंडरों को होल्ड कर कालाबाजारी कर रहे हैं। कभी सर्वर खराब होने का बहाना बनाया जाता है तो कभी गाड़ी देर से आने की बात कहकर उपभोक्ताओं को टाल दिया जाता है। बाद में वही गैस अधिक दामों पर बेचकर अवैध लाभ कमाया जा रहा है। पप्पू पांडे ने कहा कि सरकार आमजन की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और यह उसकी प्राथमिकताओं में भी शामिल है। जिला प्रशासन भी समय-समय पर गैस एजेंसियों को चेतावनी देता रहा है कि कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके बावजूद यदि गैस संचालकों की मनमानी जारी रही तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जाएगी। चौपाल में मौजूद ग्रामीणों ने भी गैस की कालाबाजारी पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर मनोज, बसंत, अनिल, शंकर, मोहन, मीणा, तेजपत्ती, सुनीता, राजू, कलावती, सिंगारी सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

राजधानी से हटेंगे चीनी सीसीटीवी कैमरे, विशेषज्ञ सलाहकार की देखरेख में तैयार होगा नया सुरक्षा खाका

नई दिल्ली । राजधानी की सड़कों और गलियों में मुस्तैद दिल्ली की तीसरी आंख अब अपना चश्मा बदलने जा रही है। अब तक शहर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे लाखों कैमरों में से चीनी तकनीक के सभी को पूरी तरह हटाने की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है अव्यवस्थित तरीके से लगे सीसीटीवी कैमरों को व्यवस्थित तरीके से लगाने के साथ ही पुराने हो चुके चीनी कैमरों को बदलकर अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएं। इन कैमरों को प्राथमिकता के आधार पर हॉटस्पॉट वाली जगहों पर स्थापित किया जाएगा। राजधानी में 2018 से अब तक दो चरणों में लगभग 2.8 लाख कैमरे लगाए गए। इनमें से पहले चरण में लगाए गए अधिकांश कैमरे चीनी कंपनियों के हैं और सिम-आधारित तकनीक पर काम करते हैं। विशेषज्ञों ने इन कैमरों के जरिए डेटा लीक होने और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित खतरे की आशंका जताई थी। सरकार का मानना है कि तकनीकी रूप से आउटडेटेड हो चुके हैं, इसलिए इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाकर आधुनिक कैमरों में बदला जाएगा। अब तक सीसीटीवी का मुख्य उपयोग अपराध होने के बाद सबूत जुटाने के लिए किया जाता था। लेकिन नई योजना के तहत, सरकार का ध्यान अपराध रोकथाम पर है। इसके लिए सरकार एक विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त करेगी जो पूरे नेटवर्क का अध्ययन करेगा। ऑडिट में यह देखा जाएगा कि किन इलाकों में कैमरों की अधिकता है और कहां ब्लाइंडस्पॉट बचे हैं। कैमरों के एंगल इस तरह तय होंगे कि अपराधियों की पहचान आसान हो और डेटा सीधे पुलिस के साथ साझा किया जा सके। ऑडिट में यह बात भी सामने आई है कि दिल्ली के कई प्रमुख चौराहों और चौराहों पर अलग-अलग एजेंसियों (जैसे दिल्ली पुलिस, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी) ने अपने-अपने कैमरे लगाए हुए हैं। एक ही खंभे पर तीन-चार कैमरे होने से न केवल बिजली को खपत बढ़ती है, बल्कि डेटा प्रबंधन में भी भारी भ्रम पैदा होता है। नई नीति के तहत इस ओवरलैपिंग को खत्म कर एक एकीकृत निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि सरकारी पैसे और संसाधनों की बचत हो सके। वर्तमान में इस विशाल नेटवर्क का रखरखाव केंद्र सरकार की संस्था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कैमरों की फुटेज 30 दिनों तक सुरक्षित रखी जाती है, जिसे जरूरत पड़ने पर पुलिस या अदालत को सौंपा जाता है। नई योजना में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कैमरों का समान वितरण और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। डेटा सुरक्षा - चीनी कैमरों और सिम-आधारित तकनीक से जासूसी और डेटा चोरी का खतरा। तकनीकी खामी- पुराने कैमरों में रात के समय विजिबिलिटी और चेहरा स्पष्ट दिखने में समस्या। असमान वितरण - कुछ रिहायशी कॉलोनियों में जरूरत से ज्यादा कैमरे, जबकि अपराध वाले हॉटस्पॉट्स अभी भी खाली। खराब स्थिति - पहले चरण (2018) में लगे कैमरों का मेंटेनेंस अब महंगा पड़ रहा है और वे बार-बार खराब हो रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत यह कदम उठाए जाएंगे.. स्मार्ट कमांड सेंटर - पूरी दिल्ली की लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग होगा। रियल-टाइम अलर्ट - संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु दिखने पर कैमरा खुद कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेगा।

सपा मुखिया अखिलेश यादव देशद्रोही तो नहीं, लेकिन उनकी देशभक्ति पर संदेह- डिप्टी सीएम केशव

प्रयागराज ।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर प्रयागराज में निशाना साधा। सपा प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केशव ने कहा कि मैं अखिलेश यादव को देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन उनकी देशभक्ति पर संदेह जरूर है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के कारण देश और दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। इस संकट से पहले जहां रोजाना 50-55 लाख गैस सिलिंडर बुक होते थे, अब यह आंकड़ा 88 लाख तक पहुंच गया है। अखिलेश यादव और या राहुल गांधी दोनों ही माहौल खराब करने और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके बयानों से देश में दहशत फैल रही है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी। केशव प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता से बाहर होने वाली है और भाजपा सत्ता में आ रही है। भाजपा के पक्ष में बने माहौल ने टीएमसी को हिलाकर रख दिया है। इसलिए वे आक्रामक रुख अपना रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त हैं, लेकिन जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। केशव प्रसाद मौर्य रविवार को परेड ग्राउंड में आयोजित सरस मेले में मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।

राहुल गांधी ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बसपा संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने इस बाबत पीएम मोदी को पत्र लिखा है।

पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान हर भारतीय के लिए बराबरी, इज्जत और हिस्सेदारी का वादा करता है। कांशीराम ने अपनी जिंदगी समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के लिए इन वादों को मतलब देने में लगा दी। ऐसा करके उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को यादा रिप्रेजेंटेटिव और इंसाफ वाला बनाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं। यह सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कांशीराम के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी, जिसने करोड़ों बहुजनों को हक, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाई। इस मांग को लेकर मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र की कॉपी शेयर की। पत्र में उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि यह पत्र आपको ठीक लगेगा। आज जब हम कांशीराम की जयंती मना रहे हैं और उनकी विरासत और योगदान पर सोच रहे हैं, तो मैं यह रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। कांशीराम ने भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल दिया। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने अपने आंदोलनों के जरिए बहुजनों और गरीबों में राजनीतिक जागरूकता फैलाई। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनका वोट, आवाज और प्रतिनिधित्व जरूरी है। यह देश सभी का बराबर है। उनकी कोशिशों की वजह से कई लोग जिन्होंने कभी सार्वजनिक जीवन में आने के बारे में नहीं सोचा था, वे राजनीति को न्याय और सम्मानता पाने के एक साधन के रूप में देखने लगे। राहुल गांधी ने कहा, कई वर्षों से दलित बुद्धिजीवी, नेता और एक्टिविस्ट कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग लगातार बनी हुई है और इसे गहराई से महसूस किया जा रहा है। हाल ही में मैं लखनऊ में एक प्रोग्राम में गया था, जहां मौजूद नेताओं और लोगों ने इस मांग को जोरदार तरीके से दोहराया, जो एक आम भावना को दिखाता है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने से हमारे देश के लिए उनके बहुत बड़े योगदान को पहचान मिलेगी।

70 से ज्यादा घर तबाह, 2 लोगों की मौत... ओडिशा में भयंकर तूफान ने मचाई तबाही

नेशनल डेस्क । ओडिशा के मयूरभंज जिले में रविवार को आए अचानक तेज तूफान ने भारी तबाही मचा दी। करंजिया इलाके में आए प्रचंड 'नॉरवेस्टर' यानी कालबैसाखी तूफान के कारण कई गांवों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। तेज हवाओं और चक्रवाती झोंकों के चलते दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जिले के किया गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अचानक उठे बवंडर जैसी तेज हवाओं ने कच्चे और फूस के बने घरों को बुरी तरह प्रभावित किया। शुरुआती आकलन में करीब 70 से अधिक मकानों के पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। तूफान की चपेट में आने से

2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर करने की तैयारी की जा रही है। तूफान के दौरान तेज हवाओं के कारण कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए, जिससे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। कई सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना भी सामने आई, जब तेज हवाओं के झोंकों से एक ऑटो-रिक्शा उछलकर पास के तालाब में जा गिरा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। तूफान के बाद स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर हालात का जायजा ले रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित परिवारों को राहत देने और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा में 15 से 19 मार्च के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।

नेपाल में दर्दनाक हादसा- मनोकामना मंदिर से लौट रहे सात भारतीय श्रद्धालुओं की मौत, करीब 200 मीटर नीचे गिरी बस

काठमांडू । नेपाल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात भारतीय श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब श्रद्धालु मनोकामना मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में कुछ नेपाली नागरिक भी घायल हुए हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार यह हादसा नेपाल के गोरखा जिले के साहिद लखन ग्रामीण नगरपालिका क्षेत्र के पास हुआ। श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक माइक्रोबस अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे लगभग 200 मीटर नीचे ढलान में गिर गई। बस में कुल 14 लोग सवार थे। इनमें से सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी यात्रियों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी श्रद्धालु मनोकामना मंदिर में दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। वाहन को

चितवन के कुरिन्टार इलाके से मंदिर तक आरक्षित किया गया था। दर्शन और पूजा करने के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में यह बड़ा हादसा हो गया। वाहन में सवार अधिकांश लोग भारतीय नागरिक थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन के ब्रेक फेल होने से यह दुर्घटना हुई। वाहन में मौजूद एक कर्मचारी ने बताया कि रास्ते में ड्राइवर ने ब्रेक सही तरीके से काम नहीं करने की शिकायत भी की थी। हालांकि उस समय यात्रियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा जिस जगह हादसा हुआ, वहां सड़क की हालत भी ठीक नहीं थी और पानी निकालने के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई थी। इन कारणों से वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया। हादसे के बाद घायलों को तुरंत चितवन के भरतपुर स्थित कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार नौ घायलों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से पांच लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। तीन घायलों को न्यूरोसर्जरी आईसीयू में भर्ती किया गया है, जबकि दो अन्य का इलाज सर्जरी आईसीयू में चल रहा है। बाकी घायलों का भी इलाज जारी है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल की टीम और जिला पुलिस कार्यालय गोरखा के जवान मौके पर पहुंचे। बचाव दल ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दांव

पश्चिम बंगाल में पुजारियों-मुअजिनों का मानदेय 500 रूपये बढ़ा, अब हर महीने 2000 मिलेंगे

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। राजनीतिक दल अपने-अपने चुनावी रण की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में जारी रैलियों और रणनीति बैठकों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत उन्होंने राज्य के पुजारी और मुअजिनों की मासिक मानदेय राशि 500 रुपये बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है। इस बात की जानकारी सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दी है। अपने पोस्ट में सीएम ने कहा कि ये लोग हमारी समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें यह सहयोग दिया जा रहा है। साथ ही, जिन्होंने नए आवेदन राय सरकार को प्रस्तुत किए थे, उन्हें भी मंजूरी दे दी गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार हर समुदाय और परंपरा का सम्मान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक को पूरा सहयोग और मान्यता मिले। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर भी बड़ा एलान किया। एक अलग पोस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ-साथ राय के शैक्षिक संस्थानों के लाखों शिक्षक और गैर-शिक्षक स्टाफ, तथा पंचायत, नगरपालिका और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों/पेंशनरों के लिए अपना वादा पूरा कर दिया है।

इसी साल मिलेगा बकाया डीए

सीएम ने कहा कि अब ये सभी लोग वेतन और भत्तों का पुनरीक्षण नियम के डीए बकाया की राशि मार्च 2026 से प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इसे लागू करने की पूरी प्रक्रिया और नियम सरकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किए गए हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि यह कदम कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है और इसका उद्देश्य सभी को समय पर आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना है।

राहुल गांधी के चाय-पकौड़ा विरोध पर साधा निशाना

गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहने के दौरान प्रदर्शन करना सही है, लेकिन इसके लिए एक मर्यादा होनी चाहिए। शाह ने राहुल गांधी के संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय-पकौड़ा खाने और ललिया एआई शिखर सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन के तरीके को गलत बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र की पवित्र जगह है और राहुल गांधी को यह तक नहीं पता कि नाश्ता कहां करना चाहिए। शाह के अनुसार, राहुल गांधी के ऐसे कामों से देश की छवि खराब होती है।

अमित शाह ने गुवाहाटी में रखी हजारों करोड़ की नई परियोजनाओं की नींव

असम । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के गुवाहाटी में कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने 15 साल के शासन के दौरान राय के स्वास्थ्य बजट से हर साल 150 करोड़ रुपये का गबन किया। शाह ने करीब 2,092 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल अपने नेताओं के परिवारों की भलाई के लिए काम करती रही, जबकि भाजपा समाज के हर वर्ग को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस ने 15 साल के शासनकाल में असम के स्वास्थ्य बजट से हर साल 150 करोड़ रुपये हड़पे- शाह

हजारों करोड़ की नई परियोजनाओं की नींव

दौरे के दौरान गृह मंत्री ने कई नए अस्पतालों का शिलान्यास भी किया। इनमें दीफू (220 करोड़), जोरहट (310 करोड़) और बारपेटा (284 करोड़) में बनने वाले सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल शामिल हैं। साथ ही, गुवाहाटी में 218 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य भवन और अभयपुरी में 115 करोड़ का नया जिला अस्पताल बनाया जाएगा। अमित शाह का पिछले चार महीनों में यह चौथा असम दौरा है, जिसे आगामी चुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर - उड़ी में सेना का बड़ा एक्शन

रात के अंधेरे में घुसपैठ की कोशिश की नाकाम, पाकिस्तानी आतंकी ढेर

जम्मू । जम्मू-कश्मीर के उड़ी सेक्टर में ऑपरेशन DIGGI-2 के दौरान भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। नियंत्रण रेखा के पास बुखार इलाके में हुई एक संयुक्त कार्रवाई में सेना के जवानों ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। सेना के अनुसार, यह आतंकवादी घुसपैठ कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने की फिराक में था। जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस को बुखार, उड़ी सेक्टर में घुसपैठ के प्रयास के संबंध में एक विशिष्ट सूचिया इनपुट प्राप्त हुआ था। इस सूचना के आधार पर भारतीय सेना और पुलिस ने 14-15 मार्च की दरमियानी रात को एक संयुक्त अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान घने जंगल में सैनिकों ने एक आतंकवादी को संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत घेराबंदी कर आतंकी को चुनौती दी। इसके जवाब में आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ के दौरान मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है। बरामदगी में एक एके सीरीज राइफल, पिस्तौल और कारतूस शामिल हैं। यह बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि आतंकवादी बड़े हमले की योजना बना रहा था। सेना ने बताया है कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बल इलाके में किसी अन्य आतंकी की मौजूदगी की आशंका के चलते तलाशी अभियान चला रहे हैं।

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान 9 अप्रैल से शुरू, बंगाल में 2 चरणों में होगा चुनाव, मतगणना 4 मई को होगी

नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग 15 मार्च (रविवार) को शाम 4:00 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा की। इसके अनुसार, मतदान 9 अप्रैल को शुरू होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव एक ही चरण में 9 अप्रैल को होंगे। तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को होगा। वहीं, पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे, जिसमें मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को निर्धारित है। आयोग ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वोटों की गिनती 4 मई को होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बताया कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कराने के लिए लगभग 25 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। इन कर्मियों में मतदान कर्मचारी, सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे, जो चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को संभालने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव वाले पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 2.19 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि मतदाताओं के लिए मतदान को सुलभ और सुचारू बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। मतदान केंद्रों की यह बड़ी संख्या, अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में होने वाली इस चुनावी प्रक्रिया के विशाल पैमाने को दर्शाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए, 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनावों को 20 से ज्यादा देशों के चुनाव आयोगों के प्रतिनिधि भी देखेंगे। इन प्रतिनिधियों को भारत में चुनावों के उत्सवपूर्ण, पारदर्शी और कुशल संचालन को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के पैमाने के बारे में बताया, और इस पूरी प्रक्रिया को चुनावों का त्योहार कहा। एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि इन चुनावों में 824 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 17.4 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे, जिससे यह देश की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रियाओं में से एक बन जाएगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार ने तैयारियों के पैमाने और खास इंतजामों की जानकारी दी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में सभी के लिए पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही, उन्होंने मतदाताओं की विविधतापूर्ण प्रोफाइल पर भी रोशनी डाली। कुमार ने कहा, आपको हमारे मतदाताओं की श्रेणियों का अंदाजा देने के लिए बता दूं कि असम, केरल, यहां तक कि पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हमारे पास 100 साल से ज्यादा उम्र के, यानी शतायु मतदाता भी हैं। 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी-खासी है... कुल मिलाकर 2.18 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होंगे। हर मतदाता के लिए औसत संख्या 750 से 850 के बीच होगी, और किसी भी हाल में यह 900 से ज्यादा नहीं होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। कुछ पोलिंग स्टेशन खास तौर पर महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। सभी पोलिंग स्टेशनों पर 100फीसदी वेबकास्टिंग की जाएगी। और कुछ पोलिंग स्टेशन हमारे दिव्यांग भाई-बहनों द्वारा भी संचालित किए जाएंगे।

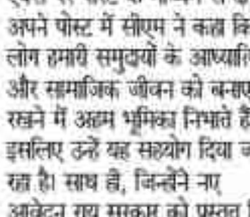

चुनाव कार्यक्रम का पूरा विवरण

1. असम - मतदान की तिथि - 9 अप्रैल; मतगणना की तिथि - 4 मई
2. तमिलनाडु - मतदान की तिथि - 23 अप्रैल; मतगणना की तिथि - 4 मई
3. पश्चिम बंगाल - मतदान की तिथि - 23 अप्रैल (पहला चरण), 29 अप्रैल (दूसरा चरण); मतगणना की तिथि - 4 मई
4. केरल - मतदान की तिथि - 9 अप्रैल; मतगणना की तिथि - 4 मई
5. पुडुचेरी - मतदान की तिथि - 9 अप्रैल; मतगणना की तिथि - 4 मई